



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 142]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 17, 1999/फाल्गुन 26, 1920

No. 142]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 17, 1999/PHALGUNA 26, 1920

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(नौवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1999

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Shipping Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 1999

का०आ० 176(अ).—जबकि मुम्बई उच्च न्यायालय ने 1999 की रिट याचिका सं. 401—शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के बारे में दिनांक 16-2-1999 के अपने आदेश द्वारा यह निर्देश दिया था कि प्रतिवादियों जिनमें अन्य यूनियनों के साथ—साथ (i) फार्वर्ड सीमेन्स यूनियन ऑफ इंडिया, मुम्बई (ii) भारतीय राष्ट्रीय नाविक यूनियन, मुम्बई और (iii) जहाजी मजदूर यूनियन, मुम्बई शामिल हैं, द्वारा प्रस्तुत मांग-पत्र पर निर्णय देने के लिए वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 150 के तहत एक न्यायाधिकरण का गठन किया जाए।

अतः, अब केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 150 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उक्त यूनियनों के मांग-पत्र पर निर्णय देने के लिए एक न्यायाधिकरण का गठन करती है जिसका मुख्यालय मुम्बई में होगा तथा महाराष्ट्र, पेट्रो कैमीकल्स कार्पोरेशन की अध्यक्ष श्रीमती कुमुद बंसल, भा.प्र.से. (महाराष्ट्र-1969) को उक्त न्यायाधिकरण के लिए नियुक्त करती है जो इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छः माह के भीतर न्यायाधिकरण का फैसला केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेंगी।

[फा.सं. सी-18018/3/99-एम टी]

एम. रामचन्द्रन, संयुक्त सचिव

S. O. 176(E).—Whereas the Mumbai High Court by its order dated 16-2-1999 in Writ Petition No. 401 of 1999—the Shipping Corporation of India and Others versus Union of India and Others has directed that a Tribunal may be constituted under Section 150 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) to adjudicate on the charter of demands submitted by respondents comprising inter-alia (i) Forward Seamen's Union of India, Mumbai, (ii) National Union of Seafarers of India, Mumbai and (iii) Jahazi Mazdoor Union, Mumbai.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 150 of the said Act, the Central Government hereby constitutes a Tribunal, with headquarters at Mumbai for the adjudication of the charter of demands of the unions cited above and appoints Smt. Kumud Bansal, IAS (Maharashtra-1969), Chairman, Maharashtra, Petro Chemicals Corporation to the said Tribunal who shall submit the award of the Tribunal to the Central Government within six months from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

[F. No. C-18018/3/99-MT]

M. RAMACHANDRAN, Jt. Secy.

